AWACS etc. from America, they are encouraging terrorist activities, they are engaged in giving training to the deserted Sikhs and other persons and allowing narcotics and other things to come to India. Pakistan authorities are also indulging in creating tension in the minds of the Indian Sikhs by utilising their own community people who are going there from foreign countries.

Therefore, through you, Madam, I would urge upon the Government to lodge a strong protest with the Pakistani authorities just to show that it is not only an anti-national but anti-Government issue, I would like that the Government of India lodges a very strong protest with the Pakistan authorities.

REFERENCE TO THE NEED TO ENCOURAGE INDIAN TOURISTS TO VISIT THE SOVIET UNION.

श्री धर्म चन्द्र प्रशान्त (जम्मू और काश्मीर) : उपसभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है ताकि एक बहुत ही आवश्यक बात मैं इस सदन में कह सकूं ।

हम भारतवासी आरम्भ से ही विदेशों में जाने में आनाकानी करते रहे हैं । उसका कारण यह था कि शायद कुछ धार्मिक विडम्बना भी हो सकती है और दूसरा धन की कमी के कारण भी हो सकता है । अभी तक रूस जिसके साथ हमारी मैत्री बढ़ रही है, वहां जाने में बहुत कम लोग जाते हैं वह इसलिये कि कुछ भारत सरकार की तरफ से उन्हें कनसेशंस नहीं हैं । जहां तक पासपोर्ट और वीसा का सवाल है उसे लेने में भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं । (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, कोई मिनिस्टर उपस्थित नहीं हमारी बात सुनने के लिए ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): I am here.

श्री राम अवधेश सिंह : यह तो एक है, एक से काम नहीं चलेगा ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (मध्य प्रदेश) : एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ।

श्री राम अवधेश सिंह : यह आपकी तरफ से डायरेक्शन होना चाहिये कि हमारी बात सुनने के लिये मिनिस्टर रहने चाहियें । एक से काम चलने वाला नहीं है । (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Government is represented here through the Minister of Parliamentary Affairs. You need not worry.

श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त : मैं जम्मू काश्मीर राज्य का रहने वाला हूं । 100 साल पहले उस वक्त के महाराजा रणधीर सिंह ने अपनी फौज के सिपाहियों को कहा था कि वह सीमा पर जायें । हमारी सीमा जो जम्मू काश्मीर की थी वह रूस के साथ मिलती थी परन्तु 1947 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया और गिलगित को उस ने अपने अधिकार में कर लिया, आज हमारी सीमा बहुत पीछे हो गई है । 100 साल पहले महाराजा रणबीर सिंह ने अपनी फौजों को कहा था कि आप सीमा पर जा कर रूस के जो सनिक हैं उन के साथ सम्पर्क रखें । परन्तु वे भाषा नहीं जानते थे इसलिये महाराजा ने कहा कि आप रूसी भाषा भी पढ़ें और उनके साथ सम्पर्क रखें । तो उस समय जितने सैनिक जम्मू काश्मीर रियासत के थे उन्होंने रूसी सैनिकों के साथ पूरा सम्पर्क रखा और बाकायदा वहां से रिपोर्ट जाती थी कि यह हुआ, वह हुआ । उसके बाद दूसरे महाराजा आए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर चार्ज लगा दिया कि महाराजा रूस के साथ षड़यंत्र कर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उनको कह

[श्री धर्मचंद प्रशांत]

रहा है कि रूस अपनी फौज भारत पर ले आए ताकि इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रभुसत्ता है उसको खत्म किया जाए उनको यहां से निकाला जाए । तो उन्होंने कहा कि 32 पत्र महाराजा ने रूस की लिखे हैं और उन पत्रों में यह था कि रूस अपनी फौज यहां पर भेजे महाराजा उनको निमंत्रण दे रहे हैं और वे उनको राहदारी दगे । महाराजा पर इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केस चलाया और चाहा कि महाराजा को हटा दिया जाए परन्तु भारत के कुछ नेताओं और समाचार-पत्रों ने महाराजा की बहुत सहायता की जिससे महाराजा बच गया पर उससे अधिकार छीन लिये गये परन्तु राजगद्दी से नहीं उतारा गया । 1947 तक यह था कि हमारी फौजें जो थीं वहां तक जाती थीं उनके साथ उनका सम्पर्क था उनकी सीमा भारत के साथ थी परन्तु 1947 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया जिससे हमारी सीमा बहुत दूर चली गई और उनके साथ सम्पर्क टूट गया । मेरा कहने का मतलब यह है कि गिलगित पर जो पाकिस्तान का अधिकार है वह एक आक्रमण था और उसको न कोई कानून और न किसी विधान से उचित ठहराया जा सकता है । यह जो गिलगित है यह रियासते काश्मीर का एक भाग था । इसको पाकिस्तान ने अपने अधिकार में कर रखा है यह जिसे सो काल्ड आज़ाद काश्मीर कहते हैं उसका एक भाग नहीं है । पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं जिनमें जिन्ना-उल-हक भी हैं वे उसको नार्दर्न एरिया आफ पाकिस्तान मानते हैं, सो काल्ड आज़ाद काश्मीर के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि आज़ाद काश्मीर डिसप्युटिड है । परन्तु उसको डिस्प्यूट में रहने नहीं दिया और डाइरेक्ट उसको अपने अधिकार में कर लिया । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की जो स्थिति है भारत सरकार उसको देखे क्योंकि पाकिस्तान ने गिलगित को डिस्प्यूटेड टेरीटरी के बजाय उसको अपने अधिकार में कर लिया है जिस पर कि वास्तव में हमारा अधिकार है । वह कायम रहे इसके लिये मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं ।

REFERENCE TO THE REPORTED STEEP INCREASE IN PRICES OF SLAG-WAX

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर खींचना चाहता हूं । महोदया, सरकार की यह नीति रही है, आज तक कि, जो लघु उद्योग हैं उनको प्रश्रय दिया जाये । अगर कुछ हानि भी उठानी पड़े तो भी उनको प्रश्रय दिया जाय ताकि उनसे अधिक से अधिक लोगों को काम मिले । यह नीति सरकार की रही है । यह भारत सरकार की 1956 की घोषित नीति है । लेकिन आज स्थिति ऐसी हो रही है कि अपने ढंग से यह सरकार इसको तोड़ती मरोड़ती रही है । महोदया, खासकर बिहार के साथ हमेशा से अन्याय होता रहा है । हमारे से मिनरल्स लिये जाते हैं और उसकी ऐवज में हमको दबाया जाता है । उधर एक समस्या खड़ी हो गई है । जो बरौनी आयल रिफाइनरी है उसके वाई-प्रोडक्ट्स से कच्चा मोम और शुद्ध मोम बनाया जाता है । वहां से जो कच्चा माल दिया जाता है, बरौनी आयल रिफाइनरी से, उसका उपयोग करीब-करीब 250 छोटे-छोटे उद्योग करते हैं । मोम बनाने वाले ये उद्योग कच्च मोम से पक्का मोम बनाते हैं, शुद्ध मोम बनाते हैं । इस तरह की 250 यूनिटें हैं । पहले से, एक तरह से यह परम्परा रही है उनको इनकरेजमेंट देने की । 1983 में वहां 80 यूनिट्स थी और सरकार ने उनको कहा कि और यूनिटें खोलो, हम तुमको राहत देंगे, प्रश्रय देंगे । तो वहां करीब करीब 225 यूनिटें खुल गईं और अब नतीजा यह हुआ है कि उनको राहत देने का काम सरकार नहीं कर रही है । वहां पब्लिक